

i:lkj Hkkj rh
Hkkj rh; i:lkj.k fuxe
vkd k'kok.kh dUæ f'keyk
27-10-2025@iknf'kd lek kj@1!"5 #&!

e&; lek kj

- मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने अधिकारियों को बजट घोषणाओं को धरातल पर उतारने के लिए निर्देश।
- प्रदेश की मानव विकास रिपोर्ट के अनुसार सतत विकास लक्ष्य सूचकांक में हिमाचल देश के शीर्ष पांच राज्यों में हुआ शामिल।
- उप-मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा— युवाओं को विदेशों में सुरक्षित रोजगार से जोड़ेगी सरकार।
- शिमला जिला के सेब बाहुल्य क्षेत्रों में एच.पी.एम.सी. का सेब सड़कों पर सड़ने के मुद्दे पर भाजपा ने राज्य सरकार पर साधा निशाना।
- पिछले करीब 2 वर्षों से आंदोलनरत दृष्टिबाधित जन संगठन ने मांगों को लेकर सचिवालय के बाहर किया प्रदर्शन।

e&;e(h

मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने वित्त वर्ष 2025–26 की बजट घोषणाओं को धरातल पर उतारने के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। वे आज शिमला में बजट घोषणाओं के कार्यान्वयन के लिए वरिष्ठ अधिकारियों के साथ आयोजित बैठक में बोल रहे थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि विकासात्मक परियोजनाओं के लिए राज्य सरकार के पास धन और संसाधनों की कोई कमी नहीं है। उन्होंने सभी विभागों को दिसंबर माह तक अपना कार्य पूरी तरह डिजिटल करने के निर्देश दिए।

lh)e

मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज प्रदेश की मानव विकास रिपोर्ट 2025 जारी की। इस रिपोर्ट में हिमाचल प्रदेश सतत विकास लक्ष्य सूचकांक पर भारत के शीर्ष पांच राज्यों में शामिल हुआ है। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह गर्व की बात है कि मानव विकास प्रतिवेदन-2025 के अनुसार हिमाचल प्रदेश का मानव विकास सूचकांक औसत शून्य दशमलव 7–8 है, जो राष्ट्रीय औसत से अधिक है। मुख्यमंत्री ने जलवायु परिवर्तन पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि यह एक गम्भीर समस्या बनकर उभरी है और समय रहते इसका स्थायी समाधान खोजना जरूरी है।

*i+e&;e(h

राज्य सरकार युवाओं को विदेशों में सुरक्षित रोजगार से जोड़ेगी। उप-मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने आज रुना जिला के पालकवाह में आयोजित हिमाचल सरकार की ओवरसीज़ रिकूमेंटमेंट ड्राइव की श्रृंखला के राज्य स्तरीय कार्यक्रम के शुभारंभ सत्र में बतौर मुख्य अतिथि ये बात कही। उप-मुख्यमंत्री ने कहा कि इस पहल के तहत विदेशों में उपलब्ध विभिन्न ट्रेडों में नौकरियों की मांग के अनुसार युवाओं का चयन किया जाएगा, ताकि कौशल व अवसर का सही तालमेल सुनिश्चित हो सके। अग्निहोत्री ने कहा कि विदेशों में स्किल की मांग है और हिमाचल के युवा इससे लाभान्वित होंगे।

[,kek.kh](#)

नगर नियोजन व आवास मंत्री राजेश धर्माणी ने कहा है कि प्रदेश सरकार औद्योगिक विकास को गति देने के लिए ठोस कदम उठा रही है। घुमारवीं विधानसभा क्षेत्र की सियूं पंचायत के भदरोग, कुठाखर और चेरी गांव का दौरा करने के बाद एक जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने ये बात कही। राजेश धर्माणी ने कहा कि कसारू में 3 सौ करोड़ रुपये की लागत से प्रदेश का पहला डिजिटल विश्वविद्यालय स्थापित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इसके लिए भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया प्रगति पर है और जल्द ही निर्माण कार्य शुरू कर दिया जाएगा।

[ekx](#)

चंबा जिला में जनजातीय पांगी घाटी की पुर्थी पंचायत के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में पिछले लगभग एक वर्ष से डॉक्टर का पद खाली है, जिसके चलते शौर, पुर्थी और रेड् पंचायतों के लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। शौर पंचायत के उप प्रधान निहाल सिंह भारद्वाज ने बताया कि घाटी में इन दिनों सर्दियों का मौसम शुरू हो गया है, ऐसे में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में डॉक्टर का न होना गंभीर विषय बना हुआ है। उन्होंने राज्य सरकार और पांगी प्रशासन से डॉक्टर के खाली पद जल्द भरने की मांग की है ताकि लोगों को घरद्वार के समीप स्वास्थ्य सुविधा मिल सके।

[Iuhy 'kek](#)

खाद्य सुरक्षा विभाग लोगों के बेहतर स्वास्थ्य के लिए कार्य कर रहा है। शिमला शहरी क्षेत्र के खाद्य सुरक्षा अधिकारी डॉ. सुनील शर्मा ने आकाशवाणी को बताया कि विभाग द्वारा समय समय पर कैटीनों, ढाबों व अन्य व्यापारिक प्रतिष्ठानों में साफ सफाई, लाइसेंस और स्वच्छ जल सहित कई तरह की जाँच की जाती है। उन्होंने कहा कि जांच के दौरान किसी भी तरह की गड़बड़ी पाए जाने पर विभाग उचित कार्रवाई करता है।

[I|. &k](#)

मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिमाचल प्रदेश में हुई आपदा के लिए 1500 करोड़ रुपए की राहत राशि देने का ऐलान किया था जो अभी तक नहीं मिली है। उन्होंने कहा कि इस राशि को दिलाने के लिए वे अपने मंत्रिमंडल के सदस्यों के साथ भाजपा सांसदों के नेतृत्व में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास जाने को तैयार हैं। सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि वे कल दिल्ली में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष से मिलकर हिमाचल प्रदेश के हितों की पैरवी करेंगे।

[Ird.rk \\$kx0drk I1rk2](#)

सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2025 आज से मनाया जा रहा है। इस दौरान प्रदेश में विभिन्न गतिविधियां आयोजित की जा रही हैं। इसी के तहत आकाशवाणी शिमला के परिसर में आज सूचना व प्रसारण मंत्रालय के उप-सचिव बृजेश गोदरा की उपस्थिति में आकाशवाणी व दूरदर्शन केन्द्र हिमाचल प्रदेश के कलस्टर हेड व उपमहानिदेशक कश्मीर सिंह ने सभी को भ्रष्टाचार की रोकथाम और उसके विरुद्ध लड़ाई को लेकर शपथ दिलाई। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार-मुक्त समाज के निर्माण के लिए सामूहिक प्रतिबद्धता को बढ़ावा देना बेहद जरूरी है।

[nf452hu](#)

दृष्टिबाधित जन संगठन अपनी मांगों को लेकर पिछले दो वर्षों से आंदोलनरत हैं। शिमला के कालीबाड़ी में ये लोग पिछले 7 सौ 4 दिनों से धरने पर बैठे हुए हैं और दृष्टिबाधितों ने आज शिमला स्थित सचिवालय के बाहर धरना प्रदर्शन किया। दृष्टिहीन जन संगठन के सचिव राजेश ठाकुर ने बताया कि वह विभिन्न विभागों में खाली पड़े दृष्टिबाधित कोटे के बैकलॉग पदों को एकमुश्त भरने की मांग कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरकार से कई दौर की वार्ता भी हो चुकी है और अब सरकार के खिलाफ उग्र प्रदर्शन किया जाएगा।

jkdl'k 6kxjk

प्रदेश भाजपा प्रवक्ता राकेश डोगरा ने शिमला जिला के सेब बाहुल्य क्षेत्रों में एच.पी.एम.सी. के सेब सड़कों पर सड़ने के मुद्दे पर राज्य सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने आरोप लगाया कि जुबल कोटखाई-रोहड़ू-रामपुर-ठियोग और चौपाल जैसे क्षेत्रों में एच.पी.एम.सी. का सेब सड़ रहा है, जबकि प्रदेश सरकार कुंभकरणी नींद सोई हुई है। राकेश डोगरा ने कहा कि सड़े हुए सेब की बोरियां नालों के पास पहुंच चुकी हैं जिससे पेयजल योजनाएं दूषित हो रही हैं और बीमारी व संक्रमण फैलने का खतरा बना हुआ है।

e&; lek kj)d #kj f7j

- मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने अधिकारियों को बजट घोषणाओं को धरातल पर उतारने के दिए निर्देश।
- प्रदेश की मानव विकास रिपोर्ट के अनुसार सतत विकास लक्ष्य सूचकांक में हिमाचल देश के शीर्ष पांच राज्यों में हुआ शामिल।
- उप-मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा— युवाओं को विदेशों में सुरक्षित रोजगार से जोड़ेगी सरकार।
- शिमला जिला के सेब बाहुल्य क्षेत्रों में एच.पी.एम.सी. का सेब सड़कों पर सड़ने के मुद्दे पर भाजपा ने राज्य सरकार पर साधा निशाना।
- पिछले करीब 2 वर्षों से आंदोलनरत दृष्टिबाधित जन संगठन ने मांगों को लेकर सचिवालय के बाहर किया प्रदर्शन।
